

समूह – 20 का शिखर सम्मेलन और दिल्ली घोषणा पत्र : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

चेनाराम मुंदलिया*

सार

समूह 20 विश्व की प्रमुख विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है जिसका गठन मूलतः 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में 1999 में किया गया था। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभावी जवाब देने के लिए इसके राष्ट्राध्यक्षों का उच्चस्तरीय सम्मेलन वाशिंगटन में हुआ। तब से लेकर आज तक यानी दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 तक निरन्तर आयोजन हो रहा है। समूह 20 का अपना कोई मुख्यालय नहीं है सदस्य देशों में बारी-बारी से किसी देश में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। 2023 में 18 वां शिखर सम्मेलन भारत में तथा 2024 में अगला सम्मेलन ब्राजील के रियो डि जेनेरो में प्रस्तावित है। दिल्ली शिखर सम्मेलन में पहली बार साझा घोषणा पत्र पर आम सहमति बनना भारत की वैश्विक स्तर पर एक कूटनीतिक सफलता रही है।

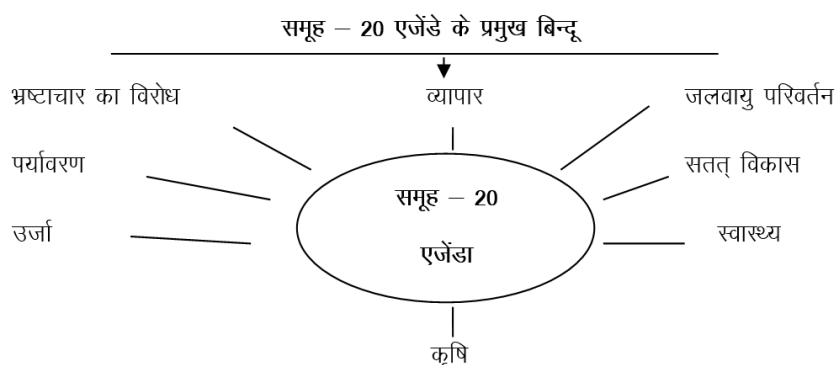
शब्दकोश: समूह-20, दिल्ली घोषणा पत्र, ट्रोइका, शेरपा ट्रैक, एफएटीएफ, आर्थिक कॉरिडोर, धारणीय विकास।

प्रस्तावना

इस समूह में 19 सदस्य देश तथा यूरोपीय संघ एवं दिल्ली शिखर सम्मेलन में सदस्यता से अफ्रीकी संघ सम्मिलित होने पर दो युनियन सदस्य हैं। भारत, चीन, इन्डोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, तुर्किये, रूस, आस्ट्रेलिया, सुयंक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, ब्रिटेन, जर्मन, इटली, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, यूरोपीयन संघ (27 सदस्यीय) तथा दिल्ली सम्मेलन में अफ्रीकी संघ (55 सदस्यीय) को सदस्यता देने पर इस समूह की वर्तमान में सदस्य संख्या 21 हो गयी है। इसी आधार पर अब इस संगठन को समूह 21 के नाम से पुकारा जाने लगा है। समूह में विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के सदस्य देश हैं। समूह – 20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत तथा विश्व व्यापार का 75 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन देशों में विश्व की करीब दो-तिहाई जनसंख्या निवास करती है। यह वैश्विक स्तर का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग मंच है जो विश्व स्तर के प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना एवं अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में प्रभावी भूमिका अदा करता है।

इस संगठन की स्थापना 1999 में एशिया महाद्वीप में आए वित्तीय संकट के बाद विभिन्न देशों के वित्त मंत्रियों एवं केन्द्रीय बैंक के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर विमर्श के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में की गयी थी। इस वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट से यह स्पष्ट हो गया था कि समन्वय केवल उच्चतर राजनीतिक स्तर पर ही सम्भव होगा तब जी-20 का राज्य सरकार के प्रमुख के स्तर पर अपग्रेड किया गया और इस समूह के नेता नियमित रूप से मिलने लगे। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मध्य पर समूह 20 के राष्ट्राध्यक्षों के स्तर तक उन्नयन किया गया और 2009 में इसे वाशिंगटन (संयुक्त राज्य अमेरिका) बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। अपने शुरुआती दौर में समूह व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केन्द्रीत था परन्तु बाद में एजेण्डे का विस्तार किया गया इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, उर्जा पर्यावरण और भ्रष्टाचार का विरोध आदि शामिल किया गया।

* सह आचार्य – राजनीति विज्ञान, राजकीय बाँगड़ महाविद्यालय, डीडवाना, राजस्थान।



एस जयशंकर ने कहा था कि यह एक वैश्विक आर्थिक मंच है न कि भू राजनीतिक मंच, ऐसे में रुस तथा युकेन युद्ध की इस मंच पर चर्चा सार्थक नहीं है। हमें मानवता के लिए काम करना है। युकेन संकट को बाली सम्मेलन की तरह दिल्ली सम्मेलन में हावी नहीं होने देना हमारी कूटनीतिक विजय थी। यह युग युद्ध का नहीं है हमें मानवता के लिए मिलकर काम करना है।

समूह – 20 की अध्यक्षता

समूह का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित होता है। समूह की अध्यक्षता सालाना सदस्यों के बीच घूमती है और देशों के एक अलग क्षेत्रीय समूह ये चुनी जाती है। इसलिए 19 सदस्यों के पांच समूहों में विभाजित किया गया है जिनमें से प्रत्येक में निम्नांकित देश शामिल है –

- समूह – 1 ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका
- समूह – 2 भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्किये
- समूह – 3 अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको
- समूह – 4 फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम।
- समूह – 5 चीन, इंडोनेशिया, जापान और कोरिया गणराज्य

यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ इसमें किसी भी क्षेत्रीय समूह का सदस्य नहीं है। प्रत्येक वर्ष एक अलग समूह का कोई अन्य देश जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करता है। प्रत्येक जी-20 प्रेसीडेंसी अन्य अतिथि देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को जी-20 की बैठक और शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

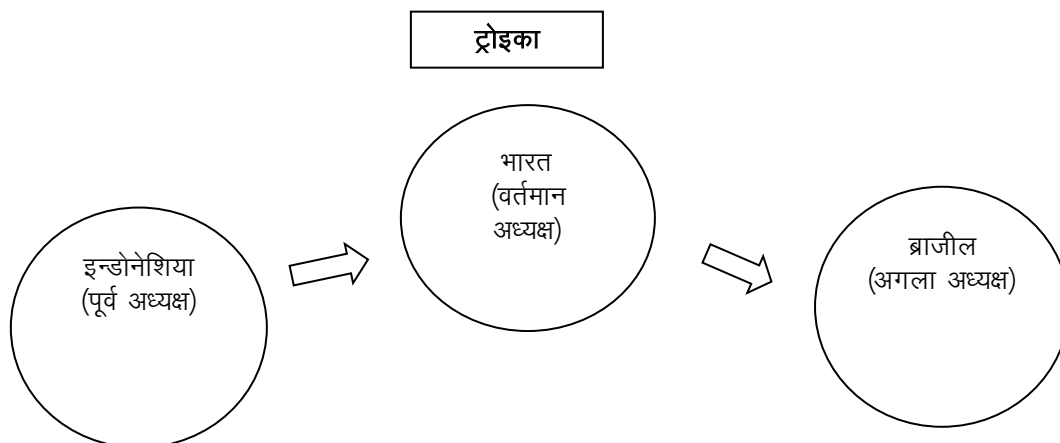
भारत समूह 2 से है जो कि 01 नवम्बर, 2023 से 30 नवम्बर, 2023 तक जी – 20 का अध्यक्ष रहेगा। भारत ने अपनी जी-20 की अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैण्ड, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ तथा क्षेत्रीय संगठन में एयू एचडीए तथा आसियान के अध्यक्षों के अलावा आईएसए, सीडीआरआई एवं एडीबी को आमंत्रित किया गया था।

जी-20 प्रेसीडेंसी अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के उपाय में जी-20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। निरन्तर सुनिश्चित करने के लिए प्रेसीडेंसी को वर्तमान, अतीत और अगले मेजवान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित किया जाता है।

क्या है ट्रोइका

ट्रोइका जी-20 की अध्यक्षता करने वाले तीन देशों का समूह है जिसमें क्रमश पीछला अध्यक्ष देश, वर्तमान में अध्यक्षता करने वाला देश तथा अगले वर्ष अध्यक्षता करने वाले देश को सम्मिलित किया जाता है।

समूह – 20 का 18 वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली – 2023



समूह – 20 की कार्यशैली

समूह 20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए जी 20 एजेन्डा का संचालन किया जाता है। इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जी 20 के दो समान्तर ट्रैक होते हैं – वित्त ट्रैक तथा शेरपा ट्रैक।

वित्त ट्रैक का नेतृत्व देश के वित्त मंत्री एवं केन्द्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा किया जाता है जबकि शेरपा ट्रैक में सभी देशों के शेरपा होता है और इसका चयन देश का लीडर करता है जो कि देश का प्रतिनिधित्व करता है। समूह 20 की प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है जो नेताओं के नीजी प्रतिनिधि होता है। दो ट्रैक के भीतर विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह है जिनमें सदस्यों सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित अतिथि देशों और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वित्त ट्रैक मुख्यतः वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठक करते हैं। दिल्ली शिखर सम्मेलन के पहले साठ शहरों में बैठक हुई जिसमें 220 के करीब मिटिंग भारत में हुई है तब दिल्ली घोषणा पत्र सामने आया।

शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं। शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और समूह 20 के इस कार्य का समन्वय करते हैं। इनके अलावा ऐसे सम्पर्क समूह है जो समूह 20 देशों के नागरिक समाज, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं। इस समूह का स्थायी सचिवालय नहीं है तथा इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है जिसमें पिछले वर्ष की अध्यक्षता तथा वर्तमान एवं अगले वर्ष अध्यक्षता करने वाले देश का क्रम होता है वर्तमान में भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका के क्रमशः हैं – इन्डोनेशिया (पूर्व अध्यक्ष) भारत (वर्तमान अध्यक्ष) ब्राजील (अगला अध्यक्ष) के रूप में सम्मिलित है। शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करता है जो कि अपने राष्ट्र के नेता के प्रतिनिधि होता है। भारत की ओर से समूह 20 में अमिताभ कांत शेरपा है।

समूह – 20 के मुख्य फोकस क्षेत्र

समूह – 20 के एजेंडा में कृषि , भ्रष्टाचार विरोध, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, उर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और निवेश जैसे सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दें प्रमुख हैं। इसी प्रकार के इसके कार्यसमूह बने हुए उनमें कृषि कार्य समूह, भ्रष्टाचार विरोधी समूह, संस्कृति कार्य समूह, विकास कार्यसमूह, डिजिटल अर्थव्यवस्था समूह, आपदा एवं आपदा नवीनीकरण कार्यसमूह, शिक्षा कार्य समूह, रोजगार कार्यसमूह, उर्जा परिवर्तन कार्यसमूह, पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्यसमूह, स्वास्थ्य कार्य समूह, स्वास्थ्य कार्यसमूह, पर्यटन कार्यसमूह, व्यापार एवं निवेश कार्यसमूह प्रमुख हैं।

समूह – 20 वित्त ट्रैक वित्त मंत्री एवं केन्द्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधि एवं विभिन्न कार्यसमूह में बैठक के माध्यम से वैश्विक व्यापक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करता है। इस ट्रैक के अन्तर्गत कार्य समूह शामिल है जिसमें फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह, इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग समूह, सतत् विकास ग्रुप, वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी, संयुक्त वित्त एवं स्वास्थ्य कार्यबल, अन्तर्राष्ट्रीय कराधान मुद्दे, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दें आदि प्रमुख है।

वित्त ट्रैक द्वारा निष्पादित कुछ प्रमुख मुद्दों में है जैसे – वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण की निगरानी, अधिक स्थिर और लचीली वैश्विक वित्तीय संरचना के लिए सुधार, समूह– 20 फ्रास्ट ट्रैक में अन्तर्राष्ट्रीय कराधान, गुणवत्तापरक अवसंरचना का वित्त पोषण दीर्घकालीन वित्तीयन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय क्षेत्र में सुधार और भावी स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए वित्त पोषण और महामारी के रोकथाम, तैयारी एवं प्रतिक्रिया में निवेश आदि।

समूह– 20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहाकार सम्मेलन

भारत की समूह 20 की मौजूदा अध्यक्षता के दौरान शुरू की गयी एक नवीन पहल है। इसका लक्ष्य समूह 20 सीएसएआर, वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रभावी संस्थागत मंच प्रदान करना है। इस शिखर सम्मेलन में रूस एवं युक्रेन युद्ध के चलते साझा घोषणा पत्र जारी करना एक चुनौतिपूर्ण कार्य था परन्तु इसे भारत की कूटनीतिक विजय ही माना जाएगा की पहली बार इस मंच का साझा कार्यक्रम जारी हो सका। घोषणा पत्र के 83 बिंदुओं को बिना किसी विरोध के सभी ने स्वीकार किया। अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए आतंकवाद को एक गम्भीर खतरा रेंखाकित करते हुए उसके सभी स्वरूप की निंदा की गयी। जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों में गति लाने तथा ईंधन के रूप में कोयले के इस्तेमाल को कम करने के प्रयास करनेकी बात इस घोषणा पत्र में की गयी वहीं वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे विकासशील देशों के संकट को प्रभावी ढंग से सुलझाने तथा तेज, सस्ते, अधिक पारदर्शी व समावेशी सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने का संकल्प इस सम्मेलन में लिया गया।

सम्मेलन से इत्तर एक कार्यक्रम में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस बनाने की घोषणा तथा एक अन्य कार्यक्रम के तहत भारत एवं अमेरिका ने चीन की बीआरआई परियोजना के प्रत्युत्तर में भारत –मध्य पूर्व – यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा अलग से एक बैठक में की। इसके माध्यम से भारत इजरायल, यूएई जॉर्डन व यूरोप के बीच व्यापार सरल होगा। संक्षेप में समूह 20 का दिल्ली शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन से वैश्विक कूटनीति में भारत की क्षमता एवं प्रतिष्ठा में चार चाँद लगाए हैं। युद्धरत रूस – युक्रेन के बीच दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति विकसित करना वैश्विक नक्शे पर भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया है। समूह 20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत एव उसकी टीम के सघन प्रयास भी इसके लिए प्रशंसनीय है। 55 देशों के समूह अफ्रीकी संघ को मंच का 21 वां सदस्य सर्वसम्मिति से बनाना भी भारत की एक बड़ी कामयाबी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जैन, बी. एम (2020) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
2. घई, यू आर (2018) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, न्यू एकेडेमिक पब्लिशिंग कंपनी, जालंधर
3. राय, अभय नारायण (2010) भारत श्रीलंका सम्बन्ध – राजीव गांधी काल के संदर्भ में, पी. एल. मिडिया।
4. दत्त, पी. वी. (2003) बदलती दुनिया में भारत की विदेश नीति, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली।
5. तिवारी, ओमप्रकाश (2006) राष्ट्रीय सुरक्षा, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. इण्डिया टुडे एवं करेंट अफेयर्स पत्रिका 2023
7. द हिन्दू, अमर उजाला एवं राजस्थान पत्रिका रिपोर्ट 2023
8. राजस्थान पत्रिका – सम्पादकीय 01 दिसम्बर, 2023

